

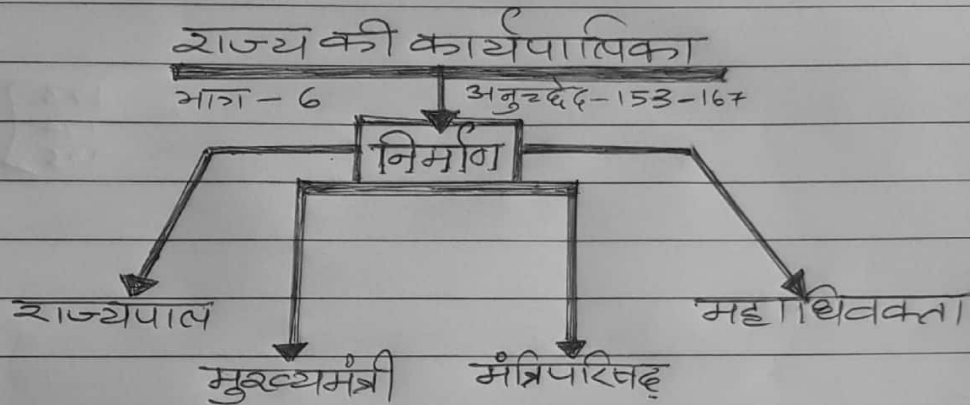
Page: 1 to 4

DATE: 01/10/2020

CLASS: B.A. (H) PART-2ND  
SUBJECT: POL. SC.  
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 10 (GOVERNOR)  
LECTURE NO. - 01 (OCTOBER)

By,  
OM KUMAR SINGH  
ASSISTANT PROFESSOR  
DEPTT. OF POL. SC.  
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR  
LNMU, DARBHANGA



राज्यपाल  
GOVERNOR

राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका

का वैधानिक प्रधान होता है जबकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया है, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना कार्य करता है।

राज्यपाल से सम्बंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद -

- 153 — राज्यों के राज्यपाल, देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है।
- 154 — राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा।

- 155 — राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान ।
- 156 — कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ।
- 157 — राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएँ ।
- 158 — राज्यपाल के पद के लिए शत्रु एवं वतनक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रावधान ।
- 159 — राज्यपाल द्वारा शपथ ।
- 160 — कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यांश निर्वाह ।
- 161 — क्षमाआदि की और कुछ मामलों में हंडाईश के निषेध, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति ।
- 164 — राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ।
- 165 — राज्यपाल द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति । महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त तक रहता है ।
- 174 — राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति ।
- 175 — सदन या सदनो में अभिभाषण का और उनको हंडाईश गैजने का राज्यपाल अकाधिकार ।
- 176 — राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।
- 201 — कोई विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आश्रित रख लिया जाना ।
- 213 — अक्षयदेशी जारी करने की राज्यपाल की शक्ति ।
- 233 — राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ।



## राज्यपाल की नियुक्ति :

अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश इसकी नियुक्ति करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह लंबे एवं राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करता है।

## योग्यताएँ एवं शर्तें :-

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- (iii) किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अन्तर्गत पद का पद न धारण करता हो।
- (iv) संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

## शपथ :-

अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल सर्वोच्च राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। वह संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ-साथ लोगों की सेवा और वसाई का वचन भी देता है।

### कार्यकाम :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में उल्लेख किया गया है कि 'राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाहपर्यंत पद धारण करेगा।'

सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु इससे पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है या राष्ट्रपति उसे कार्यमुक्त कर सकता है।

राष्ट्रपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद मरु राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल को इतने सम्बंधी प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं हैं।

### सम्भावित प्रश्न :

राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। इसकी योग्यताएं एवं शक्तियां उल्लेख कीजिए।